

06 मई 2024 : समाचार विश्लेषण

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E. संपादकीय:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

1. अब समय आ गया है कि भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय का संचालन किया जाएः
2. सूडान के गृह युद्ध का एक अवलोकनः

अर्थव्यवस्था:

1. गरीबों को धनी बनाओ बिना अमीरों को गरीब बनाएँः

F. प्रीलिम्स तथ्यः

1. भारत में कोटनाशक अवशेष सीमा के लिए कड़े मानदंड हैंः केंद्र

G. महत्वपूर्ण तथ्यः

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्नः

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्नः

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

अब समय आ गया है कि भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय का संचालन किया जाएः

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधितः

अंतर्राष्ट्रीय संबंधः

विषयः भारत के हितों पर भारतीय परिदृश्य पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां और राजनीति का प्रभाव।

मुख्य परीक्षा: भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय की आवश्यकता।

विवरणः

- थूसीडाइड्स की प्रसिद्ध टिप्पणी है, "जो राष्ट्र अपने विद्वानों और अपने योद्धाओं के बीच अंतर करता है उसकी सोच कायरों द्वारा और उसकी लड़ाई मूर्खों द्वारा लड़ी जाएगी।"
- यह विद्वत्तापूर्ण और सैन्य विशेषज्ञता को एकीकृत करने के महत्व पर जोर देता है।
- अन्य देशों ने अपने सशस्त्र बलों में रणनीतिक सोच और शैक्षणिक कठोरता को बढ़ाने के लिए रक्षा विश्वविद्यालयों की स्थापना की है।
- पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों में कई रक्षा विश्वविद्यालय होने के बावजूद, भारत में इस प्रकार के विश्वविद्यालयों का अभाव है।

व्यावसायिक सैन्य शिक्षा (Professional Military Education (PME))ः

- हालाँकि युद्ध की प्रकृति स्थिर रहती है, लेकिन इसका चरित्र लगातार बदल रहा है, जिससे सैन्य शिक्षा पर प्रीमियम (कुछ अतिरिक्त राशि खर्च करने की) की आवश्यकता होती है।
- अमेरिकी उदाहरण, विशेष रूप से 1986 का गोल्डवाटर-निकोल्स रक्षा पुनर्गठन अधिनियम और 'इके' स्केल्टन द्वारा प्रस्तावित सुधार, संरचित सैन्य शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हैं।

- भारतीय रंगमंचीकरण (Theaterisation) के लक्ष्य अमेरिका में पीएमई के विकास के साथ संरेखित हैं, जो एक बेहतर तरीके से निर्मित पीएमई सातत्य की आवश्यकता पर बल देते हैं। (Indian theaterisation-सशस्त्र बलों का रंगमंचीकरण एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लिए एकल एकीकृत कमांड संरचना के तहत सेना, वायु सेना और नौसेना का एकीकरण है।)

भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय (Indian Defence University (IDU)) की स्थापना में धीमी प्रगति:

- रक्षा सेवा विश्वविद्यालय का विचार 1967 में सामने आया था और 1999 में कारगिल संघर्ष के बाद इसे गति मिली।
- वर्ष 2010 में सिफारिशों और 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के बावजूद, आईडीयू की स्थापना में प्रगति धीमी रही है।
- हालांकि भारत अपने सशस्त्र बलों के लिए कई प्रशिक्षण संस्थानों का दावा करता है, लेकिन एक व्यापक एकीकृत पीएमई ढांचे और रणनीतिक सोच के लिए एक बहु-विषयक दृष्टिकोण की कमी है।

IDU के संचालन की आवश्यकता:

- आईडीयू एक अच्छी तरह से योग्य संकाय के साथ केंद्रीकृत सैन्य शिक्षा प्रदान करके भारत की पीएमई प्रणाली में मौजूदा अंतराल को पाट देगा।
- आईडीयू और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) के बीच तुलना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उनके उद्देश्य और पाठ्यक्रम काफी भिन्न हैं।
- आईडीयू का संचालन रक्षा तैयारियों, रणनीतिक संस्कृति को बढ़ावा देने और अंतर-सेवा एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

सारांश:

- युद्ध की बदलती प्रकृति के बीच भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय (आईडीयू) की अनुपस्थिति

चिंता पैदा करती है। अन्य देशों ने ऐसे संस्थान स्थापित किए हैं, जो भारत द्वारा आईडीयू को शीघ्रता से संचालित करने की आवश्यकता को उजागर करते हैं।

सूडान के गृह युद्ध का एक अवलोकन:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

प्रारंभिक परीक्षा: सूडान के आसपास के देश एवं सूडान का क्षेत्र।

प्रसंग:

- सूडान की पहचान का संकट और विद्रोह का इतिहास 1956 में स्वतंत्रता के बाद एक साझा दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में असमर्थता से उपजा है।
- देश ने असंख्य तख्तापलट और तख्तापलट के प्रयास देखे हैं, जिससे आंतरिक संघर्ष और सत्ता संघर्ष तेज हो गए हैं।
- महत्वपूर्ण विद्रोहों में 56 साल का विद्रोह शामिल है जिसके कारण 2011 में दक्षिण सूडान का निर्माण हुआ और 2003 में डारफुरियन विद्रोह हुआ।

शासकीय संरचना और हाशियाकरण:

- खार्टूम जैसे केंद्रीय क्षेत्रों में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की एकाग्रता के कारण सूडान की विविध आबादी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- खार्टूम जैसे केंद्रीय क्षेत्रों में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की एकाग्रता के कारण सूडान की विविध आबादी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- शांति प्राप्त करने के लिए दारफुर, दक्षिण कोर्डोफन और नुबा पर्वत सहित संघर्ष क्षेत्रों और वंचित क्षेत्रों में हाशिए पर पड़ी आबादी की चिंताओं को संबोधित करने की आवश्यकता है।
- सशस्त्र हिंसा को बढ़ावा देने वाले प्रमुख मुद्दों में हाशिए पर जाना, शासन, संसाधन साझा करना, धर्म-राज्य संबंध, भूमि विवाद और सामाजिक न्याय शामिल हैं।

सरकारी नीतियां और सैन्यीकरण:

- सूडान की प्रारंभिक सरकारों ने अरब और इस्लामी पहचान पर जोर दिया, जिससे प्रतिरोध और व्यापक असंतोष पैदा हुआ।
- 1989 के तख्तापलट ने उमर अल-बशीर को सत्ता में ला दिया, एक इस्लामी शासन की स्थापना की जिसने असंतोष को दबाने के लिए आंतरिक सुरक्षा तंत्र और मिलिशिया को नियुक्त किया।
- दारफुर और अन्य क्षेत्रों में विद्रोह को दबाने के लिए जंजावीद मिलिशिया पर अल-बशीर शासन की निर्भरता ने राज्य के सैन्यीकरण में योगदान दिया।

संक्रमण और निरंतर संघर्ष:

- 2019 में स्थापित एक संक्रमणकालीन सरकार के बावजूद, चुनौतियाँ बनी रहीं, जिसके कारण 2021 में तख्तापलट की असफल कोशिश हुई और उसके बाद सत्ता संघर्ष हुआ।
- एक शक्तिशाली मिलिशिया के रूप में रैपिड सपोर्ट फोर्स के उद्भव ने, विशेष रूप से मोहम्मद हमदान डागालो (हेमेदती) के नेतृत्व में, सूडान के लोकतंत्र में परिवर्तन को जटिल बना दिया।
- हेमेदती के उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने और आर्थिक उद्यमों के सैन्यीकरण ने मिलिशिया प्रभुत्व को और मजबूत कर दिया, जिससे सशस्त्र टकराव और अस्थिरता पैदा हुई।

भविष्य की संभावनाएँ और सिफारिशें:

- सूडान को पुनर्निर्माण और एक पारदर्शी, नागरिक नेतृत्व वाली सरकार की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है जो सभी सूडानी लोगों का प्रतिनिधित्व करती हो।

- संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करने और उपनिवेशवाद के बाद के राज्य में सभी नागरिकों के समावेश और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

सारांश:

- सूडान का गृहयुद्ध शासन की विफलताओं और पहचान संबंधी संकटों के इतिहास से उपजा है। हाशिए पर जाने और सैन्यीकरण में निहित, संक्रमणकालीन प्रयासों के बावजूद संघर्ष जारी है, जिससे समावेशी पुनर्निर्माण और शांति निर्माण के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

गरीबों को धनी बनाओ बिना अमीरों को गरीब बनाएँ:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

अर्थव्यवस्था:

विषय: समावेशी विकास और उससे उत्पन्न मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: भारत में असमानता से कैसे निपटें?

विवरण:

- भारत में चुनावी चर्चा पुनर्वितरण की अवधारणा के इर्द-गिर्द घूमती रही है, जिसमें धन की जब्ती और पुनर्वितरण के आरोप राजनीतिक बहसों पर हावी रहे हैं।
- आर्थिक असमानता विश्व स्तर पर एक गंभीर मुद्दा है, जिससे अधिक न्यायपूर्ण समाज के लिए धन अंतर को पाठने पर चर्चा की आवश्यकता होती है।
- असमानता को दूर करने के लिए दो प्राथमिक दृष्टिकोण हैं: अमीर को गरीब बनाना, गरीब को अमीर बनाना, या दोनों का संयोजन।

पुनर्वितरण पर बहस:

- ग्रालतफ़हमियाँ: राजनीतिक बयानबाजी में पुनर्वितरण के आरोपों के बावजूद, वास्तविक घोषणापत्र में ऐसे उपायों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

- मौलिक मुद्दा: राजनीतिक संबद्धता या दोषारोपण के बावजूद, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती आर्थिक खाई ध्यान देने की मांग करती है।

दृष्टिकोण में दार्शनिक अंतर:

- पेरेटो ऑस्ट्रिम बनाम ग्रोथः विकसित देश धीमी वृद्धि के कारण अक्सर "पेरेटो" मार्ग अपनाते हैं, जबकि विकासशील देशों में तेजी से विकास की क्षमता होती है, जो असमानता के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करती है।
- प्रणालीगत सुधार बनाम संपत्ति करः अमीरों पर कर लगाने या भ्रष्ट प्रणालियों को ठीक करने के माध्यम से असमानता को संबोधित करना आर्थिक निष्पक्षता पर अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
- भारत में असमानता को संबोधित करना: आर्थिक विकास और कराधानः भारत की असमानता असंतुलित आर्थिक विकास और कराधान से उत्पन्न होती है, जिसमें रोजगारहीन विकास असमानताओं को बढ़ाता है।
- नीति समाधानः प्रशिक्षुता, रोजगार प्रोत्साहन और श्रम-गहन गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसी लक्षित नीतियों के माध्यम से पूँजी-श्रम गतिशीलता को पुनर्संतुलित करना।
- कराधान सुधारः सभी क्षेत्रों से समान योगदान सुनिश्चित करते हुए आम व्यक्ति पर बोझ कम करने के लिए कराधान प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करना।
- सामाजिक सुरक्षा जालः गरीबों को समर्थन देने के लिए कल्याण कार्यक्रमों को तब तक लागू करना जब तक कि वे आर्थिक विकास से लाभान्वित न हो जाएं, विकास, कर सुधार और कुशल कल्याण वितरण के संयोजन के माध्यम से वित्त पोषित।

निष्कर्षः

- भारत में अमीर-गरीब की खाई को पाटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, न्यायसंगत कराधान और सामाजिक कल्याण पर जोर दिया जाए।
- अमीरों पर दंडात्मक कराधान को अव्यावहारिक और प्रतिकूल माना जाता है, जिसका ध्यान अमीरों की संपत्ति को कम किए बिना गरीबों को और अमीर बनाने पर होता है।

सारांश:

- पुनर्वितरण पर राजनीतिक चर्चा के बीच, भारत में बढ़ती आर्थिक असमानताओं को संबोधित करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अमीरों को दंडित किए बिना गरीबों को और अमीर बनाने के लिए आर्थिक विकास, कराधान सुधार और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को संतुलित करना महत्वपूर्ण है।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. भारत में कीटनाशक अवशेष सीमा के लिए कड़े मानदंड हैं: केंद्र

प्रसंग:

- भारत सरकार ने खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेष सीमा के संबंध में सख्त नियमों की पुष्टि की है।
- रिपोर्ट सामने आई थीं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने मसालों और जड़ी-बूटियों में उच्च स्तर के अवशेषों की अनुमति दी है।
- यह मुद्दा तब उठा जब हांगकांग के खाद्य नियामक ने कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड की उपस्थिति का हवाला देते हुए दो प्रमुख भारतीय ब्रांडों, एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों के मिश्रण पर प्रतिबंध लगा दिया।
- सिंगापुर के खाद्य नियामक ने एवरेस्ट ब्रांड के एक मसाला उत्पाद को भी वापस लेने का आदेश दिया है।

समस्याएँ:

- एफएसएआई कीटनाशक अवशेषों, विशेषकर मसालों और जड़ी-बूटियों पर अपने नियमों के संबंध में जांच के दायरे में है।
- गुणवत्ता मानदंडों के साथ एमडीएच और एवरेस्ट सहित ब्रांडेड मसालों के अनुपालन के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं।

महत्व:

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जोखिम मूल्यांकन के आधार पर विभिन्न खाद्य उत्पादों के लिए अधिकतम अवशेष सीमा अलग-अलग होती है।
- एफएसएआई द्वारा जड़ी-बूटियों और मसालों में कीटनाशक अवशेषों के काफी अधिक स्तर की अनुमति देने का दावा करने वाली रिपोर्टों को गलत और दुर्भावनापूर्ण बताया है।
- भारत को वैश्विक स्तर पर अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) के लिए सबसे कठोर मानकों में से एक पर जोर दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय (आईडीयू) की स्थापना 1967 में चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (COSC) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार की गई थी।
- आईडीयू का उद्देश्य व्यापक-आधारित रणनीतिक सोच को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विविध विषयों की पेशकश करना, विज्ञान और मानविकी का विलय करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: b

व्याख्या:

- भारत ने 1967 से एक समर्पित रक्षा विश्वविद्यालय की आवश्यकता को पहचाना है। हालाँकि भारत में अभी भी अपने स्वयं के भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय (आईडीयू) का अभाव है।

प्रश्न 2. अक्सर खबरों में देखा जाने वाला 'दारफुर' स्थित है:

- (a) सीरिया
- (b) इज़राइल
- (c) ईरान
- (d) सूडान

उत्तर: d

व्याख्या:

- दारफुर पश्चिमी सूडान का एक क्षेत्र है।

प्रश्न 3. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है।
2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय FSSAI का प्रशासनिक मंत्रालय है।
3. FSSAI भारत से निर्यात होने वाले मसालों की गुणवत्ता को नियंत्रित नहीं करता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो

- (c) सभी तीन
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: c

व्याख्या:

- तीनों कथन सही हैं।

प्रश्न 4. गाजा पट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गाजा पट्टी पूर्वी भूमध्यसागरीय बेसिन में स्थित है।
2. इसकी सीमा सीरिया, लेबनान और जॉर्डन से लगती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: a

व्याख्या:

- कथन 2 गलत है। गाजा पट्टी पूर्वी भूमध्यसागरीय बेसिन में स्थित है, जो दक्षिण-पश्चिम में मिस्र और उत्तर और पूर्व में इज़राइल के साथ सीमा साझा करती है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. वैशिक युद्ध की उभरती प्रकृति और भारत की व्यावसायिक सैन्य शिक्षा (पीएमई) प्रणाली में मौजूदा अंतराल के मद्देनजर भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता की जांच कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)[जीएस-3, विज्ञान] (Examine the necessity of establishing the Indian Defence University in light of the evolving nature of global warfare and the existing gaps in India's Professional Military Education(PME) system. (150 Words, 10 Marks)[GS-3, Science])

प्रश्न 2. सूडान में चल रहा गृह युद्ध केवल सैन्य गुटों के बीच सत्ता संघर्ष के बजाय गहरे बैठे संरचनात्मक और सामाजिक मुद्दों का प्रतिबिंब है। विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक) [जीएस-2, अंतर्राष्ट्रीय संबंध] (The ongoing civil war in Sudan is a reflection of deep-seated structural and societal issues rather than merely a power struggle between military factions. Analyze. (150 Words, 10 Marks) [GS-2, International Relations])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर किलक कर के आप अपने उत्तर BYJU'S की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)